

## RAJYA SABHA

Thursday, the 26th April, 1984/6 Vaisakha,  
1906 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, Mr.  
Chairman in the CHAIR

## ORAL ANSWERS TO QUESTION

\*61. [The questioner (Shri J. K. Jain)  
was absent. For answer, vide cols \_\_\_\_\_  
infra]

**राजनीतिक हत्याओं और उपवादियों की  
गतिविधियों को ध्यान में रखते हुये कतिपय  
अधिनियमों का संशोधन**

\*62. श्री सत्यपाल मलिक : : क्या  
गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि  
देश में चल रही उपवादियों की गतिविधियों  
तथा राजनीतिक हत्याओं को ध्यान में  
रखते हुए क्या सरकार साक्ष्य अधिनियम  
दंड प्रविष्या संहिता तथा भारतीय दंड  
संहिता में आवश्यक संशोधन करने का  
विचार कर रही है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE  
MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P.  
VENKATASUBBAIAH): There is no such  
proposal.

श्री सत्यपाल मलिक : श्रीमन्, अगर  
यह बात है जो माननीय मंत्री जी कह रहे हैं  
तो मैं जानना चाहूंगा कि जो राजनीतिक  
हत्याएं हो रही हैं या जो हत्याएं उप-  
वादियों के हाथ से हुई हैं या जो और आगे  
हत्याएं होने की संभावनाएं हैं तो क्या  
सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि  
उनको सजा दिलवाने के लिए क्या  
इंतजाम कर रही है ? क्योंकि मेरी  
जानकारी यह है, आज इस देश में जो  
खतरनाक किस्म के अपराधी हैं, जो  
गिरोहबंद आदमी हैं जिनके पास ताकत है  
वह अगर कत्ल करता है तो जो मौजूदा  
कानून है उसके तहत 90 फीसदी से  
ज्यादा मामले छूटे जा रहे हैं अदालतों में ।  
उपवादियों ने जो कत्ल किये हैं उनमें से  
अधिकांश मामलों में चार्जशीट भी नहीं  
सभी हैं, निरंकारी बाबा की हत्या का  
276 RS—1.

फैसला अभी तक नहीं हो पाया है ।  
जो लोग बड़े से बड़े आदमियों को धमकी  
देते हुए नहीं डरते हैं उनके खिलाफ  
कोई कार्रवाई होगी इस देश में, इसमें  
मुझे शुबहा है । इसलिए मैं जानना  
चाहूंगा कि आप इन लोगों को सजा  
दिलाने के लिये कानून से तरीके सोच  
रहे हैं जिससे आप यह एसर्टन कर सकें  
इन्होंने जो अपराध किया है उसमें सजा  
दिलवा दें ?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, in  
order to meet the situation that is obtaining in  
Punjab, the Government have taken several  
measures. So far as IPC is concerned, there  
are ample provisions in it under which  
deterrent action can be taken against those  
who indulge in acts of arson, kidnapping,  
dacoity etc Apart from that, so far as Punjab  
is concerned, additional measures are also  
available, for instance, the Punjab (Disturbed  
Areas) Act...

MR. CHAIRMAN: Acts do not catch  
criminals.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Re-  
cently, we have amended the National  
Security Act through Ordinance. That  
Ordinance has been passed into law in the  
Lok Sabha yesterday. According to this  
amended Act a person can be detained  
without reference being made to the Advisory  
Board for a longer period. As it is his period  
of detention is upto six months. But if the  
Advisory Board upholds the order, the  
maximum period of detention could be upto  
two years under the amended law. With all  
these measures we hope that those who  
indulge in acts of arson and violence could be  
apprehended. This new Ordinance is in force  
and 38 persons have been detained under this.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:

The question is not about National Security  
Act. The question is about amending the  
Evidence Act, etc.

MR. CHAIRMAN: I know you are very  
anxious to do something. But let Mr. Malik  
have his question.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY:  
But the answer to his question must come.

MR. CHAIRMAN; I think Mr. Malik can take care of his own supplementary.

**श्री सत्यपाल मलिक :** श्रीमान्, मुझे माफ करेंगे, एक पुलिस का दरोगा इससे बेहतर जवाब देता ... (व्यवधान) । मेरा सवाल यह था कि (व्यवधान)

**कुमारी सरोज खापड़ें :** आप ऐसा लैंग्वेज इस्तमाल करेंगे, यह आशा नहीं थी ... (व्यवधान)

**श्री सत्यपाल मलिक :** मैंने यह कहा है कि मेरे सवाल का जवाब एक दरोगा बेहतर देता क्योंकि उसको मामले की जानकारी होती है, उसको गृह मंत्री से मामले की बेहतर जानकारी होती है । मेरा सवाल यह था कि जो ताकतवर क्रिमिनल्स होते हैं, चाहे वे राजनीतिक कत्ल करते हों या किसी और इरादे से कत्ल करते हों उनको आप सजा दिलवायें । अभी जो मौजूदा तरीका है, जैसा कि इमिनेन्ट जूरिस्ट्स यहां पर बैठे हुए हैं, मैं सरकार से आश्वस्त होना चाहता हूं कि क्या आप उसको सजा दिलवाएंगे ? आज का जो मौजूदा चलन है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की मुझे जानकारी है, जो बड़े-बड़े डकैत होते हैं, क्रिमिनल्स होते हैं, वे 90 फीसदी मामलों में छूट जाते हैं । बीस-बीस कत्ल करते हुए दिल्ली में वे छूट जाते हैं । उनकी फेहरिस्त और नाम दे सकता हूं । जो ताकतवर क्रिमिनल्स कत्ल करते हैं । उनको पोलिटिकल पैट्रॉनेज होती है, पुलिस को सपोर्ट होती है, इंटेलिजेन्स की सपोर्ट होती है, उनके पोछे तमाम दल होते हैं । प्रिवेंटिव डिटेन्शन के बाद वे हीरो होकर निकलते हैं । इसलिए मेरा सवाल यह है कि जो इस तरह के कत्ल करते हैं उनको आप क्या सजा देते हैं जिससे इस तरह के कत्ल न

हों ? इसके लिए यह अनश्वर करने जरूरी है कि जो इस तरह के कत्ल होते हैं उनके करने वालों को सजा दिलाई जाये ? आपके सामने अगर कोई चार्ज बिचाराधीन नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके लिए स्पीडी ट्रायल करने के लिए आप स्पेशल ट्राइब्यूनल बना सकते हैं और इन स्पेशल ट्राइब्यूनल्स में मुकदमों की सुनवाई कमरा में हो सकती है । जिस तरह से करप्शन में होता है या गवर्नमेंट के सीक्रेट एक्ट में होता है उस तरह की ट्रायल हो सकती है । चूंकि आम आदमी में यह हिम्मत नहीं है कि वह किसी एक्स्ट्राजुडिजिटल के खिलाफ गवाही दे सके । अगर आपके सामने इस तरह की कोई बात बिचाराधीन नहीं है तो मैं खुद के नाम से आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो आदमी सबसे ताकतवर हो गया है, किसी को भी मार देता है, गिरफ्तार होकर छूट जाता है, उसके संबंध में अभी तक आपने नहीं सोचा है तो क्या मेरे सुझाव की रोशनी में सोचने की इजाजत करेंगे ?

SHRI P. C. SETHI: Sir, the honourable Member has given a good suggestion. We would certainly try to consider it and act on it.

As far as the political patronage of the criminals is concerned, I absolutely deny this charge and, Sir, I want to say that we are doing everything possible to apprehend the culprits and see that they are convicted. It is for the law courts to decide, Sir, whether the charge against them is proved or not and if the charge is not proved, certainly they release them and there we are helpless.

**श्री सत्यपाल मलिक :** श्रीमान्, यह गलत हो जायगा, रिकार्ड पर गलत बात चली जायगी । मेरा पोलिटिकल पैट्रॉनेज से कहने का मतलब यह नहीं था कि आप पैट्रॉनेज दे रहे हैं । जो किलिंग पोलिटिकल

नेचर की हैं वे किन्हीं मांगों को लेकर होती हैं, खास तरह के संगठन और खास तरह की पेट्रोनेज उनको हासिल होती है। चूंकि पोलिटिकल मूवमेंट के तहत ये किलिंग होती हैं इसलिए उस लिहाज से आप अपने जवाब को ठीक कर लें।

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** मेरे खयाल से उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। जहां तक मैं समझी उन्होंने कहा कि आपका मुख्य मुद्दा यह था कि कोई तरीका निकले जिससे इन लोगों को ठीक से सजा मिले। आजकल बेल पर या दूसरे किसी बहाने ये आसानी से छूट जाते हैं। चाहे दबाव से हो या कोई और कारण हो यह मालूम नहीं लेकिन इसमें मैं बिल्कुल माननीय सदस्य से सहमत हूं कि बहुत से ऐसे केसेज हैं जिनमें पुलिस को भी काफी कठिनाई होती है। मुझ को स्वयं किसी ने कहा कि हमने फजां जने को पकड़वाया और थोड़े दिनों के बाद कोर्ट से छोड़ दिया गया।

**श्री समापति :** उसको आप एमेन्ड कीजिये बेल को स्ट्रिक्ट कीजिये।

**श्रीमती इंदिरा गांधी :** स्ट्रिक्ट करना होगा या क्या करना होगा, इस पर गौर तो कर रहे हैं, वैसे किसी माननीय सदस्य-गण के सुझाव हों तो सोचेंगे।

SHRI SANKAR PRASAD MITRA; Sir, I appreciate what the Prime Minister has slated just now. The first answer to the question given by the honourable Minister of State for Home Affairs was that there was no proposal under consideration and he referred to the National Security Act which is an Act relating to preventive detention. Sir, laws have to be amended keeping in view the realities of the sil nation. In view of the activities of terrorists and other disintegrating forces which are taking place in Punjab and in other parts of the country, would the hon. Minister of Home Affairs consider whether the question of amendment of all

the statutes mentioned this particular question should be referred to the Law Commission to suggest necessary amendments, if any?

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: Sir, this is a suggestion for consideration.

**श्री वीरेंद्र वर्मा :** श्रीमान, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा था, माननीय गृह मंत्री जी की ओर से जो उत्तर प्राप्त हुआ है, जो उत्तर उन्होंने दिया है, उसमें पंजाब की प्राब्लम को सल्व करने के लिये उन्होंने नेशनल सेक्युरिटी ऐक्ट में अमेंडमेंट करने का सुझाव बताया है। लेकिन यह प्रश्न केवल पंजाब का नहीं है। यह प्रश्न दिल्ली का है, जहां कि हरबंस सिंह मनचंदा का काल हुआ कुछ दिन पेश्तर और यह प्रश्न सारे देश का है जहां कि लोग-बाग शहादत देने नहीं जाते, गवाही देते हुए डरते हैं और लोग-बाग उसकी शिनाख्त नहीं करते, वह बहुत डरते हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे पूरे देश भर के परि-प्रेक्ष्य में इस प्रकार का कोई ऐक्शन लेंगे, जिस प्रकार का वे कह रहे हैं कि हम पंजाब में ले रहे हैं, जिससे कि इस समस्या का कोई ठीक सोल्यूशन निकल सके?

SHRI P. C. SETHI: As far as Mr. Manchanda's matter is concerned, important clues are available and we are pursuing them. As far as the action to be taken against criminals in this respect is concerned, it is a State subject. We would certainly pass on the suggestion of the hon. Member to the State Government concerned, so that they can act upon it.

MR. CHAIRMAN: There are no two opinions on this, and I think we need not discuss it further. I will give one more chance. Yes—you are jumping up so much.

SHRI SHANKARRAO NARAYANRAO DESHMUKH: We are experiencing these difficulties even in Maharashtra because a lot of complaints are lodged with the police stations. The offence which

was committed is never brought in the record. Therefore, my suggestion is that all these offences may be made non-bailable and proper entries made when the First Information Report is given to the police station. Otherwise it will be very difficult. Anybody can go and approach the police station against the person concerned who is bailed out and all these multiple offences arise. Therefore, I suggest that whenever a complaint is lodged with the police station it may be taken as it is given by the person concerned and the offences may be made non-bailable.

SHRI P. VENKATASUBBAIAH: It is being considered. I may tell for the information of the hon. House that various provisions have already been made stringent by amending the Act in respect of Punjab.

MR. CHAIRMAN: Next question. This is a Question Hour, not 'Suggestion Hour'.

#### M/s. I.T.C. Limited

63. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state;

(a) whether Government have taken any action against M/s. Indian Tobacco Company Limited for setting up two small scale units without proper licence; and

(b) if not, what are the reasons there for?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) Small Scale industrial undertakings and ancillary industrial undertakings are exempted from the licensing provisions of the Industries (Development & Regulation) Act, 1951. However, these exemptions are not available to a small scale industrial unit or an ancillary which is a subsidiary of or owned or controlled by any other undertaking.

In view of this position M/s. Indian Tobacco Company Limited would not be exempted from the licensing provisions of the Act if they were to set up any small scale industrial undertaking as defined under the Act.

According to a recent study carried out by the Indian Institute of Public Administration M/s. ITC has set up two small scale units.

This is being looked into.

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, एक तरफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की प्रोटेक्शन के लिए सरकार ने काफी व्यवस्था की है। छोटे उद्योगों को बड़े उद्योग हड़प न जाएं इसके लिए सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके बावजूद मन्त्री महोदय ने स्वीकार किया है कि इण्डियन तम्बाकू कम्पनी ने दो तरह की स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की स्थापना की है बिना लाइसेंस के, अतः आई०डी०आर० एक्ट और एम०आर०टी०पी० एक्ट का भी उल्लंघन इसके अन्तर्गत आ जाता है, उसकी छानबीन कर रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहूंगा कि वह प्रोडक्शन केपेसिटी क्या है और यह अनलाइसेंसड जो स्थापना की है आप कब तक उसकी छानबीन कर लेंगे? इसके साथ दूसरा जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि इण्डियन तम्बाकू कम्पनी ने अपनी इन्सिलेरी यूनिट्स भी कई जगहों पर लगा रखी हैं और वहां से माल भी मंगवाते हैं और ओवर-प्रोडक्शन भी यह कर रहे हैं, ओवर पेकेजिंग भी कर रहे हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इसकी भी छानबीन करेंगे?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, मुझे ज्ञात है कि माननीय सदस्य को इस विशेष प्रतिष्ठान के सम्बन्ध में काफी चिन्ता है और मैंने इसीलिए तारीख 15 मार्च और 22 मार्च को अतारंकित प्रश्नों के जरिये और 8 मार्च को तारंकित प्रश्न के जरिये उनकी जिज्ञासा को शान्त करने का प्रयत्न किया। आज भी उन्होंने प्रश्न पूछा है उसके तदनुरूप मैंने उत्तर देने का प्रयत्न किया है। सारी बातों की जांच हो रही है। एक समिति का गठन